

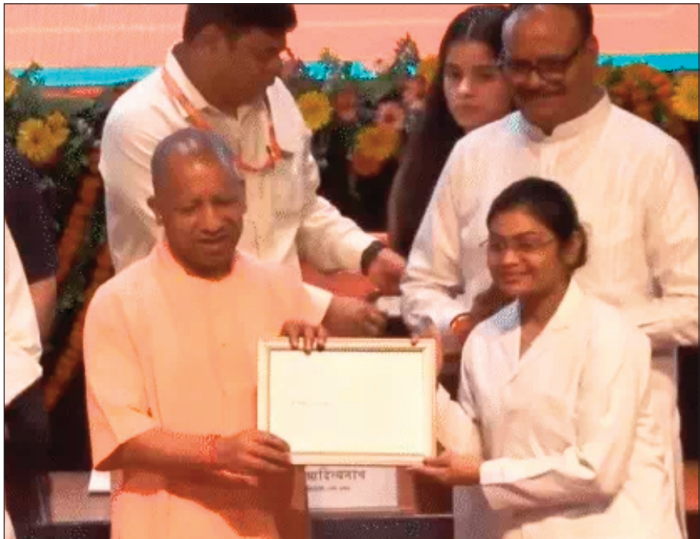
गाड़ी में पेट्रोल है, तो लाइन क्यों लगाना : योगी

लोग लाँकडाउन की अफवाह फैला रहे, लखनऊ में जॉइनिंग लेटर बांटे

लखनऊ। सीएम योगी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया आधुनिक संस्थान के चयनित नर्सिंग अधिकारियों को जॉइनिंग लेटर बांटे। रविवार को यह कार्यक्रम लखनऊ के लोकभवन में हुआ। कुल 665 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया। इनमें 345 पुरुष एवं 320 महिला अभ्यर्थी हैं। सीएम योगी ने 20 अभ्यर्थियों को सीधे जॉइनिंग लेटर सौंपे। बाकी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जॉइनिंग लेटर भेजे जाएंगे। योगी ने कहा कि पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के परिणाम सबके सामने होते हैं। हमने 9 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी। चयन प्रक्रिया पर विरोधी भी सवाल नहीं उठा सकता। नियुक्ति पारदर्शी होने से ही इसमें कोट की भी दखल नहीं है। योगी ने कहा- दुनिया संकट में है, उथल-पुथल और संशय का माहौल है। तमाम देशों ने काम के घंटे कम कर दिए हैं। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों की भी हालत खराब है। लेकिन, भारत बिना रुके चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की एक्सजाइज ड्यूटी कम की है। इसका फायदा सभी वर्गों को मिल रहा। मोदी को रोकने के लिए किस तरह निम्न स्तर के प्रयास हो रहे हैं? क्या-क्या अफवाह फैलाई जा रही है? कह रहे हैं कि लाँकडाउन लग जाएगा, सिलेंडर में गैस कम कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि सिलेंडर 25 दिन चलना है, तो 5वें दिन क्यों लाइन में खड़े हो रहे हैं? जब पेट्रोल गाड़ी में पूरा है, तो फिर लाइन में में क्यों लग रहे हैं? इन अफवाहबाजों से सावधान और सतर्क रहना होगा। जब देश की लीडरशिप आपके साथ है, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? जनता ने उन्हें सरकार से बेदखल कर दिया, अब वे अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाना भी राष्ट्रद्रोह है। लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया- 42280 आवेदन आए थे। 14 राज्यों के 34 शहरों में परीक्षा कराई गई थी। इनमें से 665 का सिलेक्शन हुआ। चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि लोहिया संस्थान पीजीआई के बाद सबसे बड़ा है।

इन अभ्यर्थियों को योगी ने जॉइनिंग लेटर दिए

सीएम योगी के हाथों जॉइनिंग लेटर पाने वालों में प्रियंका सिंह, मनीष कुमार, लक्ष्मण राम चौधरी, मोहम्मद आलम, तनु, संध्या जोशी, देवराज गुर्जर, देवेश कुमार, जय प्रकाश सिंह, धर्मेन्द्र काजला, कुमारी अनामिका यादव, दीप्ति देवी, प्रतिमा कश्यप, आकांक्षा, ऋषि राज गौतम, आराध्या सिंह, प्रियंका चौधरी, विवेक कुमार गौड़, संध्या सिंह और शर्मिष्ठा सिद्धी की शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन नियुक्तियों से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ बढ़ेगा। इससे मरीजों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।



लोकभवन में जॉइनिंग लेटर बांटे सीएम योगी। कुल 665 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया है।

डिप्टी सीएम बोले- जेवर एयरपोर्ट से भैया को दर्द हो गया

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप सभी एक बड़े संस्थान से जुड़ रहे हैं। यूपी कैसे बदलाव लाया? यहाँ 2017 पहले क्या हालत थे? क्या हमारी बेटी शाम को सुरक्षित बाहर जा सकती थी? नौकरी भी भैया-भतीजे की पची पर लगती थी नौकरी के लिए इटावा से सैफई तक भैया-भतीजे के चक्कर लगाने पड़ते थे। नौकरी के



दो एलपीजी जहाज करीब 94 हजार टन गैस लेकर होमुंज पार कर चुके हैं। बीडब्ल्यू टीवाईआर 31 मार्च तक मुंबई पहुंचेगा, जबकि बीडब्ल्यू ईएलएम अप्रैल तक न्यू बीच सरकार ने भी साफ कहा है कि देश में गैस और ईंधन की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सरकारी जानकारी के मुताबिक, बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम नाम के

>> (शेष पेज 04 पर)



समय दिया। कहा- अगर 15 दिन में जाट शब्द नहीं लगा तो 16वें दिन पंचायत होगी। इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। इस दौरान करीब 45 निमंत्रित कर धरना प्रदर्शन होता रहा। वहीं इस मामले पर नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने मंच से कहा- पुलिस ने जाट शब्द हटा दिया। वो तो बालियान जी अपने आप बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को ही हटवा देंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)



जेवर एयरपोर्ट से 1 लाख को रोजगार मिलेगा

सीएम ने कहा- यूपी में कल सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है। हमारा राज्य सबसे बड़ा है, तो हम काम भी सबसे बड़ा करेंगे। एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जेवर पहले प्रदेश का सबसे बड़ा अपराध का केंद्र था। शाम को वहाँ से कोई गुजरता नहीं था। आज उसे निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाया है। वहाँ फिल्म सिटी बन रही। सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी उसके पास हुआ है।

गड़बड़ी करने वालों की क्या हालत करते हैं, किसी से छिपा नहीं

योगी ने कहा- 2017 से पहले ज्यादातर भर्ती बांधित थी। यूपी को 9 लाख मैनपावर मिलने से बीमार राज्य को देश का ग्रोथ इंजन बना दिया। जिस राज्य के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं होते थे, अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय तीन गुना है। भर्ती परीक्षा में किसी तरह का दखल भी नहीं है। हर हफ्ते नियुक्ति पत्र वितरित किया जाता है। भर्ती आयोग पर शासन की तीसरी नजर रहती है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करे। कोई युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करे।

सीएम ने कहा- मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश नोएडा नहीं गए, लेकिन विभाजनकारी राजनीति के लिए आज नोएडा पहुंच गए। जेपीएनआईसी बिल्डिंग जय प्रकाश नारायण के नाम पर बनाई। उसका डीपीआर 200 करोड़ था, लेकिन उसमें 800 करोड़ खर्च हो गया। अभी भी अधूरी है। यह सपा का विकास का मॉडल है। ये किस मुंह से विकास की बात करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। एक समय तेल के बिना जनता लाचार हो जाती थी, अब सेमीकंडक्टर के बिना लाचार हो जाती है। शरीमा सिद्धी की ने कहा- यवन बहुत पारदर्शी हुआ है। मैं आर्मी से हूं। मैं यूपी में सेटल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की बहुत गलत तस्वीर बनी थी।

अखिलेश मुख्यमंत्री रहते नोएडा नहीं गए, आज पहुंच गए

गोमती रिवर फ्रंट में 300 करोड़ का डीपीआर था, 1400 करोड़ खर्च हो गया। फिर भी अधूरा पड़ा है। यह जनता की गाढ़ी कमाई पर डकैती है। नौकरी निकलते ही वसूली पर निकल पड़ते थे। आज अमेठी की यादव बेटी का भी चयन हुआ है। लेकिन, उसका 2017 से पहले चयन नहीं हो सकता था। क्योंकि, उसके घरवाले पैसा नहीं दे सकते थे। मैंने कह रखा है कि अगर कहीं गलती हुई तो ऐसी हालत करूंगा जो नजीर बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से भैया को दर्द हो गया। बयानबाजी कर रहे हैं।

है। आपको जनता को बताना है कि यूपी में कमल है, भाजपा है और सीएम योगी हैं। तभी प्रदेश सुरक्षित है। यूपी आज सुरक्षित हाथ में है, योगीजी के हाथ में है। यह संफेद कोट शांति का प्रतीक है। जेवर एयरपोर्ट से भैया को दर्द हो गया। बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि यूपी में रहने वाला हर कोई व्यक्ति गर्व कर रहा है।

होर्मुज संकट के बीच भारत को बड़ी राहत दो और एलपीजी टैंकर खाड़ी से खाना

जानकारी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। देश के दो और एलपीजी टैंकर सुरक्षित रास्ता पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये टैंकर देश की एक दिन की रसोई गैस की जरूरत पूरी करने जितनी गैस लेकर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने भी साफ कहा है कि देश में गैस और ईंधन की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सरकारी जानकारी के मुताबिक, बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम नाम के

पंजाब-बरनाला में जैक से उठाई जा रही बिल्डिंग गिरी

बरनाला। बरनाला में आज (रविवार) सुबह एक मकान गिरने से 3 लोग उसके मलबे में दब गए। इससे तीनों लोगों की मौत हो गई। ये तीनों मकान में अंदर सोए हुए थे। इन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इनकी मौत की पुष्टि की। मकाना हटाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची थीं। उन्होंने जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटवाया। अधिकारियों ने 3 शव बरामद होने के बाद भी कई घंटे तक जेसीबी चलवाई, ताकि यदि कोई और भी मलबे में दबा हो तो उसे भी निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि मकान की नींव धंस जाने के बाद उसे जैक से ऊपर उठाने का काम चल रहा था।

284 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव हारे अधीर रंजन को बहरामपुर से टिकट बंगाल में कांग्रेस का ऐलान-ए-जंग

तमसा संकेत, एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट पर प्रदीप प्रसाद को उतारकर कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला पेश करने की कोशिश की है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खुद चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी की वापसी की कमान संभालेंगे। चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने एक ही बार में 284 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने दार्जिलिंग से मशहूर चर्चा को। प्रदेश में कांग्रेस इस बार सभी 294 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है।



से गौतम भट्टाचार्य, आसनसोल दक्षिण से सौविक मुखर्जी और आसनसोल उत्तर से प्रसेनजीत पुरतोन्दी को भी मैदान में उतारा। इससे पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर शनिवार को विस्तृत चर्चा की। प्रदेश में कांग्रेस इस बार सभी 294 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है।

सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

बैठक के बाद कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, 'आज सोईसी की बैठक हुई, सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई, आठ को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की घोषणा आज रात या कल सुबह तक की जाएगी।' मीर ने कहा कि पार्टी को 294 विधानसभा सीटों के लिए 2,500 आवेदन मिले हैं। उनका कहना था, 'हम पश्चिम बंगाल में सभी 294 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। यह शुरू से ही राज्य में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा थी।' भवानीपुर के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर मीर ने कहा कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बड़े नेता के रूप में देखती है। इस सीट पर तुषमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पलककड़ के लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। कल महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोपों के चलते कांग्रेस को उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। इस वजह से महिलाओं को सावधान रहना चाहिए।

कांग्रेस ने जारी की 284 उम्मीदवारों की सूची

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों का एलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। हेमताबाद से अनामिका राय को, जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली को, तुषानगंज से देबेन्द्रनाथ को और दिनहाटा से हरिहर राय को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची रविवार शाम को जारी कर दी। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं सीएम ममता के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है।

नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगाई स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलने होंगे

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई हैं और स्कूलों-कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलकर नेपाली में रखने का आदेश दिया गया है। सरकार ने शनिवार रात को जारी आदेश में कहा कि यह सभी फैसले अपने 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत लिए हैं, जिसका मकसद शिक्षा को राजनीति से दूर रखना और इसे बेहतर बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब स्कूल और कॉलेजों में किसी भी तरह की



नेपाल में पिछले साल हजारों शिक्षकों ने स्कूलों का केंद्रीय लोकल लेवल पर देने का विरोध किया था।

राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों को 60 दिनों के अंदर अपने दफ्तर कॉलेज कैम्पस से हटाने होंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)



सम्पादकीय

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए इसे उचित ही भारत की नई ऊर्जा का प्रतीक कहा। इस एयरपोर्ट की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं बढ़ गई थी, क्योंकि दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव बहुत बढ़ गया था। इसकी आवश्यकता इसलिए थी थी ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बल दिया जा सके। एयरपोर्ट महज आवागमन की सुविधा भर नहीं होते, वे प्रगति को नए पंख भी प्रदान करते हैं। यह एयरपोर्ट एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र के लिए उपलब्धि भी है और अवसर भी। इसके परे-पूरे आसार दिख रहे हैं कि नोएडा एयरपोर्ट इस क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करने के साथ ही यहां के युवाओं एवं कारोबारियों को तरक्की के नए अवसर भी प्रदान करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निःसंदेह यह भी उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पिछले कुछ समय से देश में हवाई अड्डों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। आज से 15 साल पहले देश में लगभग 75 एयरपोर्ट थे, आज उनकी संख्या 160 से अधिक हो चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि देश प्रगति कर रहा है और हवाई संपर्क नए-नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। आज के युग में यह धारणा सही नहीं कि हवाई यात्रा सिर्फ धनी वर्ग के लिए ही संभव है। वास्तव में अब यह आम आदमी की भी जरूरत बन गई है। इसमें संदेह नहीं कि देश में हवाई यात्रा सुविधा का विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी उड्डयन क्षेत्र में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। इसका संकेत प्रधानमंत्री के इस कथन से मिलता है कि अभी अपने देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। यह आवश्यकजनक है कि आज भी 85 प्रतिशत हवाई जहाजों को सर्विसिंग के लिए विदेश भेजना पड़ता है। यह अच्छा हुआ कि नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर एमआरओ (मेटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल) सुविधा का भी उद्घाटन हुआ। यह सुविधा देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी के साथ इस पर भी सभी राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की परिकल्पना एवं उनके क्रियान्वयन में इतना अंतर क्यों हो जाता है? नोएडा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव 2001 में राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किया था। इसके बाद के मुख्यमंत्रियों ने भी पहल की, लेकिन किसी कारणों से बात आगे नहीं बढ़ सकी और इस तरह 25 वर्ष की देर हुई। यह देर राष्ट्रीय संसाधनों पर भारी ही पड़ी।

विश्व को संकट में डालने वाला युद्ध

यदि पश्चिम एशिया संकट के चलते ऊर्जा संकट कायम रहा तो दुनिया भर में उद्योग-धंधों के बंद होने का सिलसिला तेज होने के साथ लोगों की परेशानी अत्यधिक बढ़ जाएगी। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले लगभग एक माह से जारी युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रोकेने की कोशिश करते तो दिख रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल होते नहीं नजर आ रहे हैं। इसका कारण उनका विरोधाभासी और अविश्वसनीय रवैया है। वे ईरान को धमका भी रहे हैं और उसे युद्ध विराम की पेशकश भी कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से बातचीत का हवाला देते हुए पहले उसके बिजली और ऊर्जा ठिकानों पर पांच दिनों तक हमले टालने की घोषणा की, फिर इस अवधि को और आगे बढ़ा दिया। इस बीच उन्होंने ईरान के समक्ष जो 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, उसके जवाब में उसने भी अपनी पांच शर्तें रख दीं। 15 सूत्रीय प्रस्ताव और पांच शर्तों के चलते दोनों पक्षों के बीच किसी सार्थक बातचीत के आसार कम ही हैं, क्योंकि दोनों के बीच भरोसे का अभाव है। समस्या यह भी है कि ईरान की किसी बात का भरोसा नहीं। ईरान ने यह समझ लिया है कि वह समुद्री मार्ग होर्मुज पर अपना दबाव बनाए रखकर और उसे बाधित कर अमेरिका को झुका सकता है, क्योंकि इस मार्ग के बंद होने से उपजाऊ ऊर्जा संकट विश्वव्यापी रूप ले चुका है। अमेरिका की मानें तो वह कई मध्यस्थों के जरिये ईरान से बात कर रहा है। इन मध्यस्थों में मिस्र, तुर्किए के साथ



पाकिस्तान का भी नाम है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अमेरिका के लिए उपयोगी है। अमेरिका उसके जरिये ईरान में दखल देने की स्थिति में है। एक समय अमेरिका ने पाकिस्तान के सहारे ही अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था। माना जाता है कि ईरान को निशाने पर लेने की रणनीति के कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई थी। जो भी हो, पाकिस्तान भले ही परमाणु हथियारों से संपन्न एक मात्र इस्लामी देश होने के कारण अपने को मुस्लिम देशों के बीच विशिष्ट समझता हो, लेकिन उसकी अंतर-राष्ट्रीय साख चौपट है और वह बिल्कुल भी विश्वसनीय देश नहीं, इसीलिए वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकता है कि स्थिति में नहीं। खुद उसके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच केवल संदेशों का आदान-प्रदान कर रहा है। ऐसा करते हुए वह अमेरिका से अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करे तो हैरानी नहीं। वह अपने फायदे के लिए खुद का इस्तेमाल करने और दोस्ती के नाम पर धोखा देने में माहिर है।

■ संजय गुप्त

युद्ध के माहौल में महावीर के दर्शन की उपादेयता

66 जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता एवं संतुलन स्थापित रख सके, जो मौन की साधना और शरीर को तपाने के लिए तत्पर हो। जो पुरुषार्थ के द्वारा न केवल अपना भाग्य बदलना जानता हो, बल्कि संपूर्ण मानवता के उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना रखता हो।

इस सम्बन्ध में...

बिहार में नीतीश के बाद कौन ?

ऐसा माना जाता है कि आगामी 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में जो चर्चाएं हैं - वह यह कि मुख्यमंत्री पद भाजपा के खाते में जायेगा। जदयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत जदयू की ओर से दो उप मुख्यमंत्री होंगे। लघु विभाग और विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है पर ऐसा माना जाता है कि इन मामलों में यथार्थस्थिति कायम रहेगी, यानी यह दोनों महत्वपूर्ण पद भाजपा के पास ही रहेंगे। यह सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, महत्वपूर्ण यह कि यदि मुख्यमंत्री का पद भाजपा के खाते में जायेगा तो उसकी ओर से मुख्यमंत्री कौन ? चर्चाओं के अनुसार मुख्यमंत्री तो भाजपा का होगा पर नीतीश कुमार की सहमति इस मामले में आवश्यक रूप से होगी। ऐसा माना जाता है कि इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद हैं और अपनी इस पसंद का इजहार नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। अहम सवाल यह कि क्या बिहार का आगामी मुख्यमंत्री भाजपा का पसंद का नहीं, नीतीश कुमार की पसंद का होगा। यदि सम्राट चौधरी भाजपा की भी पसंद हों, तो बात और है लेकिन यदि ऐसा नहीं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवाकर प्रकारंतर से बिहार की सत्ता पर पूरी तरह पकड़ बनाये रखना चाहते हैं और इस तरह से कहीं-न-कहीं अपने बेटे को सत्ता के केन्द्र में बनाये रखना चाहेंगे। उपरोक्त संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिर में बिहार में कौन-सा नेता ऐसा है जो मुख्यमंत्री पद के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हो। भाजपा के शुभचिंतकों और बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों की राय में भाजपा की दृष्टि से केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सर्वाधिक उपयुक्त कहे जा सकते हैं। इसमें पहली बड़ी बात यह कि नित्यानंद राय भाजपा के कांडर से आये हैं जबकि सम्राट चौधरी दूसरे दलों से होते हुये भाजपा में आये हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि यदि कोई बड़ी वजह न हो, या अपरिहार्य परिस्थिति न हो, तो ऐसे पदों पर



कांडर से आये नेताओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई हिमंता विश्वा शर्मा जैसा व्यक्तित्व हो तो बात अलग है पर हिमंता को भी असम में पांच साल मंत्री बनाने के बाद और पूरी तरह उनकी क्षमता का आकलन करने के पश्चात ही वर्ष 2021 में भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था। सम्राट चौधरी को मुख्यंत्री बनाने के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इससे लव-कुश यानी कुर्मी-कुश-वाहा का समीकरण मजबूत रहेगा। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते यह समीकरण मजबूत था क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद कुर्मी-कुशवाहा की सर्वाधिक संख्या है। लेकिन बड़ी सच्चाई यह कि यादवों को छोड़कर सिर्फ कुर्मी-कुशवाहा ही नहीं अन्य पिछड़ी जातियाँ भी अधिसंख्य एनडीए के साथ हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि नित्यानंद राय को जो यादव समुदाय से आते हैं, यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो इससे कुर्मी-कुशवाहा समेत अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन एनडीए के प्रति कम हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचना दूर की कौड़ी होगी। वस्तुतः यदि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो

यादव समुदाय जो अभी मूलतः लालू यादव के साथ हैं, उसमें बड़ा विभाजन होकर एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आ सकता है। ऐसा इसलिए भी कि अब बिहार में लालू और उनके परिवार के लिये सत्ता दूर की कौड़ी है। फिर लोग उगतते सूरज को सलाम करते हैं। जहाँ तक प्रश्न इस बात की इससे दूसरी पिछड़ी जातियों के छिटकने का प्रश्न है तो लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऐसा राजद के शासनकाल में यादवों के प्रभुत्व और एकाधिकार के चालते हुआ था। वास्तविकता है कि जब भाजपा का मुख्यमंत्री यादव जाति से होगा तो इस बात की दूर-दूर तक संभावना नहीं कि उसमें राजनीति या प्रशासन में यादवों का एकाधिकार हो जायेगा जिसकी प्रतिक्रिया दूसरी पिछड़ी एवं अन्य जातियों में होगी। इस तरह से व्यापक जनसमर्थन और सैद्धांतिक दृष्टि से नित्यानंद राय बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में नीतीश कुमार को भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और भाजपा को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनाने देना चाहिए। आगे भाजपा कोई ऐसा भी फैसला कर सकती है जो राजस्थान की तरह अप्रत्याशित हो।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट - आधुनिक भारत की नई उड़ान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके माध्यम से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान माना जा रहा है। इस विकास से प्रदेश का ही नहीं देश का विकास भी संभव हो सकेगा? देश की तरक्की में कम्प्यूटिकेशन यानी यातायात को सुगम बनाना स्वाभाविक ही वह क्षेत्र और देश स्वयं तरक्की के पंख लगा लेता है। आज उसी अध्याय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को बीमारू छवि से बाहर

निकालेगा। प्रदेश की छवि में चार चांद लगेंगे जैसा कि बताया जा रहा है, अप्रैल के अंत में फ्लाइट्स शुरू होने के बाद यह देश का पांचवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। चारों फेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 5000 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पहले फेज के बाद इस एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ होगी। फाइनल फेज पूरी होने के बाद यह 7 करोड़ से अधिक यात्री क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। उड़ानें शुरू होने के बाद तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य का सबसे बड़ा एंविग्रेशन हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर

प्रदेश को 'बीमारू' छवि से बाहर निकालकर 'विकसित प्रदेश' की दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है, और जब देश का सबसे बड़ा राज्य आर्थिक रूप से सफल होगा, तो स्वाभाविक है कि भारत की समग्र प्रगति भी तेज होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन होने के बाद अब अप्रैल माह के अंत तक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 65 शहरों के लिए उड़ान शुरू किए जाने का दावा है। पहले चरण में देश के 10 शहरों के लिए सेवा शुरू होगी। शुरुआत में केवल घरेलू और कार्गो उड़ानें ही संचालित होगी। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे तो देश में एयरपोर्ट अलग-अलग मानकों के आधार पर तय किए जाते हैं। इनमें यात्री क्षमता, क्षेत्रफल और उड़ानों की संख्या शामिल होती है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं, क्षेत्रफल के लिहाज से हैदराबाद एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। उड़ानों की दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट हैं। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सबसे बड़ा माना जाएगा। देश के पांच सबसे बड़े एयरपोर्ट होंगे। सबसे पहले, यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार और निवेश के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। अभी तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अत्यधिक दबाव रहता है लेकिन जेवर एयरपोर्ट उस दबाव को कम करेगा और क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे निर्यात, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, यह परियोजना रोजगार के विशाल अवसर पैदा करेगी। निर्माण चरण से लेकर संचालन तक लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों—जैसे ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़—में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। तीसरा, यह एयरपोर्ट 'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेल नेटवर्क से जुड़कर यह क्षेत्र एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित होगा। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को अपने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचाने में आसानी होगी। चौथा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। जब वैश्विक कंपनियां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं।

स्वाद आदि के लिए हत्या न तो करें और न ही करवाएं और हत्या से उत्पन्न वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करें। एक बार महावीर और उनका शिष्य गोशालक एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। जैसे ही दोनों एक पौधे के पास से गुजर रहे थे। शिष्य से दुश्मन बन चुके गोशालक ने महावीर से कहा, यह पौधा देखिए, क्या सोचते हैं आप, इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? महावीर आंख बंद करके उस पौधे के पास खड़े हो गए, और कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, फूल लगेंगे। गोशालक ने महावीर का कहा सत्य न हो,

इसलिये तत्काल पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, और जोर-जोर से हंसने लगा। महावीर उसे



मैं फिर उसे उखाड़ फेंकूंगा या नहीं? तब महावीर ने कहा, यह सोचना व्यर्थ है। अनिवार्य यह है कि यह पौधा

देखकर मुस्कराए। सात दिन बाद दोनों उसी रास्ते से लौट रहे थे। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे, जहां गोशालक ने पौधा उखाड़ा था, उन्होंने देखा कि वह पौधा खड़ा है। इस बीच तेज वर्षा हुई थी, उसकी जड़ों को वापस जमीन ने पकड़ लिया, इसलिए वह पौधा खड़ा हो गया था। महावीर फिर आंख बंद करके उसके पास खड़े हो गए। पौधे को खड़ा देखकर गोशालक बहुत परेशान हुआ। गोशालक की उस पौधे को दोबारा उखाड़ फेंकने की हिम्मत न पड़ी। महावीर हंसते हुए आगे बढ़े। गोशालक ने इस बार हंसी का कारण जानने के लिए उनसे पूछा, आपने क्या देखा कि

अभी जीना चाहता है, इसमें जीने की ऊर्जा है, और जिजीविषा है। तुम इसे दुबारा उखाड़ फेंक सकते हो या नहीं-यह तुम पर निर्भर है। लेकिन पौधा जीना चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। तुम पौधे से कमजोर सिद्ध हुए और हार गए। और जीवन हमेशा ही जीतता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी है, आशावादी रहना। महावीर का संपूर्ण जीवन स्व और पर के अभ्युदय की जीवंत प्रेरणा है। लाखों-लाखों लोगों को उन्होंने अपने आलोक से आलोकित किया है। उनके मन में संपूर्ण प्राणिमात्र के प्रति सहअस्तित्व की भावना थी। आज मनुष्य जिन समस्याओं से और जिन जटिल परिस्थितियों से घिरा हुआ है उन सबका समाधान महावीर के दर्शन और सिद्धांतों में समाहित है। जरूरी है कि हम महावीर ने जो उपदेश दिये उन्हें जीवन और आचरण में उतारें। हर व्यक्ति महावीर बनने की तैयारी करे, तभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। महावीर वही व्यक्ति बन सकता है जो लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो, जिसमें कष्टों को सहने की क्षमता हो। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता एवं संतुलन स्थापित रख सके, जो मौन की साधना और शरीर को तपाने के लिए तत्पर हो। जो पुरुषार्थ के द्वारा न केवल अपना भाग्य बदलना जानता हो, बल्कि संपूर्ण मानवता के उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना रखता हो। भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन तप और ध्यान की पराक्रमा है इसलिए वह स्वतः प्रेरणादायी है। उनके उपदेश जीवनसंशर्षा हैं जिनमें जीवन की समस्याओं का समाधान निहित है। वे चिन्मय दीपक हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को हरता है। वे सचमुच प्रकाश के तेजस्वी पंुज और सार्वभौम धर्म के प्रणेता हैं। वे इस सृष्टि के मानव-मन के दुःख-विमोचक हैं। पदार्थ के अभाव से उत्पन्न दुःख को सद्भाव से मिटाया जा सकता है, श्रम से मिटाया जा सकता है किंतु पदार्थ की आसक्ति से उत्पन्न दुःख को कैसे मिटाया जाए? इसके लिए महावीर के दर्शन की अत्यंत उपादेयता है।

ललित गर्ग

यही वजह है कि...

सड़कों से गायब हुए फुटपाथ : अतिक्रमण पर आंख बंद करके बैठा प्रशासन

सड़कों से गायब होते फुटपाथ आज भारत के शहरी जीवन की एक कठोर सच्चाई बन चुके हैं, और अभी तक की स्थिति तक उपलब्ध नवीनतम सरकारी रिपोर्टें, नीतिगत दस्तावेजों और विश्वसनीय अध्ययनों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्या तो नई है और न ही आकस्मिक, बल्कि यह लगातार उपेक्षा, कमजोर शहरी नियोजन और प्रशासनिक निष्क्रियता का परिणाम है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट “रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022” के अनुसार देश में कुल सड़क दुर्घटना मृत्यु में लगभग 19 प्रतिशत पैदल यात्रियों की हिस्सेदारी रही। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर पाँच में से लगभग एक व्यक्ति, जो सड़क पर जान गंवा रहा है, वह पैदल चल रहा था। यह आँकड़ा केवल दुर्घटना का नहीं, बल्कि शहरी ढाँचे की प्राथमिकताओं का दर्पण है, जहाँ पैदल चलने वालों की सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है। भारत के शहरी ढाँचे में पैदल यात्रियों की भूमिका को समझना आवश्यक है। विभिन्न शहरी परिवहन अध्ययनों, जैसे कि “नैशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006” और उसके बाद के संशोधित दृष्टिकोणों में यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय शहरों में 20 से 40 प्रतिशत तक यात्राएँ छोटी दूरी की होती हैं, जिन्हें लोग पैदल या गैर-मोटर चालित साधनों से तय करते हैं। इसके बावजूद, शहरों की सड़क योजना मुख्यतः मोटर वाहनों की गति और संख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। नीति और व्यवहार के इस अंतर ने फुटपाथों को ‘वैकल्पिक’ बना दिया है, जबकि वे वास्तव में शहरी जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं। परिणामस्वरूप, आज अधिकांश शहरों में या तो



फुटपाथ मौजूद ही नहीं हैं, या वे इतने खंडित, संकरे और अव्यवस्थित हैं कि उनका उपयोग करना जोखिम भरा हो जाता है। फुटपाथों के अतिक्रमण की समस्या इस संकट को और गहरा करती है। शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले फुटपाथ, व्यवहार में बहुउद्देशीय और अनियंत्रित उपयोग के स्थल बन गए हैं। उन पर रेहड़ी-पटरी, अस्थायी दुकानें, अवैध पार्किंग, निर्माण सामग्री और कई बार स्थायी संरचनाएँ तक देखी जा सकती हैं। यह स्थिति केवल अवैधता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शहरी अर्थव्यवस्था और नियोजन के बीच असंतुलन का भी संकेत है। “Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014” ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित तरीके से निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थान दिया जाए, ताकि उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहे और सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण भी नियंत्रित हो। लेकिन 2026 तक उपलब्ध विभिन्न राज्य स्तरीय क्रियान्वयन रिपोर्टों और मीडिया विश्लेषणों से यह स्पष्ट है कि अधिकांश शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटीयें पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं और न ही पर्याप्त वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। इस नीति-क्रि-यान्वयन अंतर ने फुटपाथों को अव्यवस्था के हवाले कर दिया है।



